



कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

-ज्ञापन-

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/2013
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 10/जुलाई/ 2017

✓ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

0000

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार जगदलपुर से सीलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम परपा, पटवारी हल्का नंबर 13, राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ), तहसील जगदलपुर की निजी भूमि रकबा 0.32 हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के नियम 24 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल से प्राप्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। कृपया उक्त सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट कलेक्टर बस्तर के वेबसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

K.
5/7/17
(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

कार्यालय तहसीलदार, जगदलपुर जिला-बस्तर ।

क्रमांक
प्रति

म / तहसीलदार / 2017

// जापन //

जगदलपुर, दिनांक 13.06.2017

कलेक्टर,
(भू-अर्जन शाखा)
बस्तर जिला,
जगदलपुर ।

विषय :- समाजिक समाधात निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में ।
संदर्भ :- आपका आदेश क्रमांक क/भू-अर्जन/21/2013 जगदलपुर दिनांक
22.04.2017

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) तट रेल्वे विशाखापट्टनम के प्रस्ताव अनुसार जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिये ग्राम परपा पटवारी हल्का नंबर 13 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ) तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.83 हेक्टेयर में से 0.32 हेक्टेयर उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापट्टनम के पक्ष में अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय -2 धारा 4 से 6 एवं भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाधात निर्धारण, सहमति एवं जनसुनवाई) नियम 2016 में निहित प्रावधानों के तहत प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक सामाधात अध्ययन कर सामाजिक समाधात निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत दल गठित किया गया है ।

दिनांक 27.06.2017 को गठित दल के द्वारा निर्धारित क्षेत्र का सामाजिक समाधात अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया । पंचनामा की प्रति संलग्न है ।

स्थल निरीक्षण से यह पाया गया कि प्रभावित भूमि ग्राम परपा पटवारी हल्का नंबर 13 राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ) तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा नंबर 106 रकबा 1.83 हेक्टेयर में से 0.32 हेक्टेयर राजपति त्रिपाठी पति स्व० हरिप्रसाद त्रिपाठी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । उक्त भूमि रेल्वे लाईन से लगी हुई है । प्रभावित भूमि से अर्जन से दुरस्थ अंचल क्षेत्रों में

—2—

यातायात एवं परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होगी । इसके साथ ही व्यापार तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि होगी । सुचारु रूप से परिवहन का विकास होने से स्थानीय लोगों को रोजगार तथा शिक्षा के नये अवसर उपलब्ध होंगे । जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक विकास में वृद्धि होगी । प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वृक्ष तथा अचल सम्पत्ति स्थित नहीं है । जिसे भूमि अर्जन से पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है । अतः उपरोक्त सभी सकारात्मक पक्षों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का भू-अर्जन किया जाना उचित होगा ।

प्रतिवेदन मय दस्तावेजों के साथ सादर सम्प्रेषित है ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार ।

Madhi
तहसीलदार,
जगदलपुर

प्ररूप-दो
(नियम 18 देखिये)
भाग-क-पूर्व लिखित सहमति/घोषणा प्ररूप

स.क्रं.	संबंधित व्यक्ति का विवरण	
1	अधिनियम की धारा 3 (ग) (एक) एवं (पांच) के अनुसार व्यक्तियों के नाम	श्रीमती राजपाल त्रिपाठी
2	पति/पत्नी का नाम	स्व. हरि प्रसाद त्रिपाठी
3	पिता/मर्रा का नाम	स्व. राम सुख शुक्ला
4	पता	गंगानगर वाड गीदम
5	गाम/बस्ती	मिड जगदलपुर
6	ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगरीय	परपा
7	तहसील/तम्बुका	परपा
8	जिला	जगदलपुर
9	परिवार में अन्य सदस्यों के आयु सहित नाम (बच्चों और आश्रित व्यक्तों सहित)	① अरिवलेश त्रिपाठी 44 वर्ष ② अराधना त्रिपाठी पति अरिवलेश 40 वर्ष ③ अश्विनी त्रिपाठी पति अरिवलेश 13 वर्ष ④ अश्विनी त्रिपाठी पति अरिवलेश 10 वर्ष ⑤ विरोध त्रिपाठी पति 21 वर्ष ⑥ मिथिलेश त्रिपाठी 40 वर्ष ⑦ सविता त्रिपाठी पति मिथिलेश 30 वर्ष ⑧ अनिल त्रिपाठी 36 वर्ष ⑨ विवेक त्रिपाठी 30 वर्ष ⑩ रिपुन त्रिपाठी पति मिथिलेश 12 वर्ष
10	स्वामित्व भूमि का विस्तार	
11	अर्जन के लिए क्षेत्र	0.32 है.
12	प्लॉट नं.	106
13	अधिकारों का अभिलेख	भूमि स्वामी
14	विवादित भूमि, यदि कोई हो	नहीं
15	पट्टा/लीज/अनुदान, यदि कोई हो	नहीं
16	कोई अन्य अधिकार, अभिधृति सहित, यदि कोई हो	नहीं
17	शासन द्वारा मेरी भूमि के अर्जन के संबंध में, मैं निम्नलिखित कथन करना चाहता हूँ (कृपया गोला लगाएं) :	
	(एक) मैंने इस सहमति प्ररूप की अंतर्वस्तु को पढ़ लिया है/पढ़कर सुना दिया गया है और भाषा में मुझे समझा दिया गया है और	हां ✓ नहीं
	(दो) मैं इस अर्जन के लिए सहमत नहीं हूँ।	हां नहीं
	(तीन) मैं इस अर्जन से सहमत हूँ।	हां ✓ नहीं

	① अखिलेश - A - ⑤ अनिल - A ② आराधना - A - ⑥ विशेष (राजपती त्रिपाठी) ③ मिथिलेश - M - ⑦ विवेक - (राजपती त्रिपाठी) ④ लबिता - सविता - अंगूठे का निशान और तारीख
18	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन, निबंधन एवं शर्तें प्रतिकर एवं अन्य निबंधन तथा शर्त प्ररूप से संलग्न होनी चाहिए।
	हस्ताक्षरित प्ररूप महेश्वर जिला पदधारी के हस्ताक्षर तारीख
	यदि वे सहमति देने से इंकार करते हैं या यदि मैं यह कथन चुनते हूँ कि वे इस प्ररूप पर सहमति नहीं देते हैं तो किसी व्यक्ति को धमकाना या उन्हें कोई हानि पहुंचाना विधि के अधीन एक अपराध है। इसमें, कोई धमकी या ऐसा कृत्य जिससे उन्हें धन की हानि पहुंचे, जो उन्हें शारीरिक रूप से चोटिल करें या कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को क्षति पहुंचे, सम्मिलित है। यदि इस प्रकार की कोई धमकी दी गई है तो यह प्ररूप अकृत और शून्य है।

प्ररूप-तीन

सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन

(नियम 23 देखिये)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण :-

क) कुल जनसंख्या	(एक) पुरुष 569	(दो) महिला 720
ख) बच्चों की संख्या	(एक) पुरुष 36	(दो) महिला 48
ग) जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा. 792	(दो) ज.जा. 05
	(तीन) अ.पि.व. 27	(चार) अन्य 465
घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू 1289	(दो) मुस्लिम नहीं
	(तीन) सिक्ख नहीं	(चार) ईसाई नहीं
	(पांच) बौद्ध नहीं	(छः) अन्य नहीं

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या 245

3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या 23

4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या 1

5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या 338

6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन नहीं

7. प्रशासनिक संगठन नहीं

8. राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी

9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य नहीं

10. भूमि का उपयोग— (एक) कृषि भूमि 632.380

(दो) पड़त भूमि 47.600

(तीन) सिंचित एक फसली भूमि 6.610

(चार) सिंचित दुफसली भूमि 35.200

(पांच) असिंचित भूमि 511.060

11. जोत का आकार— (एक) लघु कृषकों की संख्या 79
 (दो) सीमांत कृषकों की संख्या 108
 (तीन) कुल खातों की संख्या 316
 (चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या 01
 (पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक से दी जाये) 44 23
12. पशुधन — (एक) पशुधन की संख्या 278
 (दो) दुधारु पशुधन की संख्या 20
13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार — नहीं
14. पलायन — नहीं
15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी — हाँ
16. खाद्य सुरक्षा — हाँ
17. अन्य स्थानीय रोजगार — नहीं
18. मजदूरी दर — शासन द्वारा निर्धारित दर
19. ऋण तक पहुंच — उपलब्ध है।
20. परिवहन एवं सड़क — उपलब्ध है।
21. सिंचाई — निजी सिंचाई
22. बाजार तक पहुंच — उपलब्ध है।
23. पर्यटन स्थल — नहीं
24. सहकारी संस्थाएं — शा. उचित मूल्य की दुकान
25. रहन-सहन—
 (एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा साधारण
 (दो) गृह

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान

भवन उपलब्ध है

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल

मत्ता मंदिर उपलब्ध है

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यदि) नहीं

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यदि) 30-2 22.01 उपलब्ध है 03 01

(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा ।

पुलिस थाना पर्याप्त , -

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि जीविका और आय पर समाधान—

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार

— कृषि एवं मजदूरी

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके

— कृषि

(ग) आय के स्तर

— न्यूनतम + मध्यम

(घ) खाद्य सुरक्षा

— हाँ

(ङ.) जीवन निर्वाह का स्तर

— साधा 205

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण -

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच -

उपलब्ध है।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात -

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात लागू नहीं

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लागू नहीं

3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात—

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता

लागू नहीं

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता

लागू नहीं

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव

लागू नहीं

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली

लागू नहीं

(ङ.) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात

लागू नहीं

4. स्वास्थ्य समाघात—

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात

बागू नहीं

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात

बागू नहीं

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात—

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण

बागू नहीं

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन

बागू नहीं

(ग) आर्थिक, पारिस्थिकी संतुलन में परिवर्तन

बागू नहीं

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात

बागू नहीं

(ङ.) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप

बागू नहीं

(च) विस्थापन का तनाव

बागू नहीं

(छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात

बागू नहीं

6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात —

(क) पूर्व-सन्निर्माण चरण

बागू नहीं

(ख) सन्निर्माण चरण

बागू नहीं

(ग) प्रवर्तन चरण

बागू नहीं

(घ) कार्य से हटाने वाला चरण

बागू नहीं

(ङ.) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात

बागू नहीं

(च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

सुनीता प्रियाम
ग्राम पंचायत परपा
जनपद पंचायत जगदलपुर (छ.ग.)

सुनीता प्रियाम
ग्राम पंचायत परपा
जनपद पंचायत जगदलपुर (छ.ग.)

महसिलदार
जगदलपुर

प्रमुख

पंचनामा

आज दिनांक 27/5/2017 को ग्राम-परपा पंचन-13 परपा
 शान्तिमें जगदलपुर में तहसील- जगदलपुर जिला-बस्तर में उप मुख्य
 अभियंता (निर्माण) एवं तहसील विभागाध्यक्ष के परस्पर अनुसार
 जगदलपुर से मिलक क्षेत्र तक इन्फ्रा रेल लाइन निर्माण कार्य के लिए
 ख.नं. 106 बकदा 0.32 हे. भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ करने के एवं
 भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा
 पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय-2 धारा 4 से 6
 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर
 तथा पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाधात निर्धारण सभा
 तथा जन सुनवाई) नियम 2016 में निहित प्रावधानों के तहत प्रभावित
 क्षेत्र का सामाजिक समाधात अध्ययन करने हेतु कार्यवाही क्षेत्र बस्तर
 जिला जगदलपुर के अधेश्वर/ड/भू.अर्जन/21/2013 जगदलपुर दिनांक
 22/4/2017 के अनुसार गठित रेल द्वारा प्रभावित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण
 किया गया। स्थल निरीक्षण में यह पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र के
 अर्जन से बस्तर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात एवं परिवहन
 सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके साथ ही व्यापार तथा व्यवसाय में
 वृद्धि होगी। जिससे शासन के राजस्व में वृद्धि होगी। सुचारु रूप
 से परिवहन का विकास होने से स्थानीय लोगों के जीवनगार तथा
 के नये अवसर उपलब्ध होंगे। जिससे लोगों के सामाजिक, आर्थिक
 विकास में वृद्धि होगी। प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हानि
 अथवा संपत्ति क्षति नहीं है। जिससे भूमि अर्जन से पर्यावरण को
 किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त सभी सकारात्मक
 पक्षों को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों का भू.अर्जन किया जाना उचित
 होगा। पंचनामा स्थल पर पढ़कर सुनाया गया।

(Signature)
 विवेक त्रिपाठी
 उप/स्वात अनुभाग-
 जी.पी. राजपति निपाटी
 ज. वि. 9. 106
 24/05/17

(Signature)
 तहसील जगदलपुर

(Signature)
 भुवनेश्वर
 पदवारी ह. 93
 दिनांक 24/5/17

(Signature)
 सोनाद
 सरपंच
 ग्राम पंचायत परपा